[Shri R. Venkataraman]

Indian enterprises upto 40 per cent without bringing in any sophisticated technology. We have also said that they can keep a foreign account here in dollars and foreign currency and can take it back. We have also offered incentives by way of rate of interest on the money which they hold here. All these have really helped and if you look at remittances in the year 1980 it is that which has gone to really save a very difficult balance of payments position. In 1980-81 as against a normal 2,000 crores last year we had almost double the amount by way of remittances from abroad. Therefore, every effort is being made and I am happy to say it has borne fruit.

12.52 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 9th March, 1981, will consist of :

(1) General discussion on the General Budget for 1981-82.

(2) Submission to the vote of the House of the Demands for Grants on Account (General) for 1981-82.

(3) Consideration of any item of Business carried over from the Order Paper of today.

(4) Discussion and voting on :

(a) Supplementary Demands for Grants (General) for 1980-81.

(b) Demands for Excess Grants (General) for 1977-78 and 1978-79.

(c) Demands for Grants (Railways) for 1981-82.

(d) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1980-81,

(e) Demands for Excess Grants (Railways) for 1977-78 and 1978-79.

(5) Discussion on the Resolution regarding recommendations of the Railway Convention Committee.

SHRI R. K. MHALGI (Thane) : Sir, there are two points in my notice but I am going to mention only one. Sir I would like the Agriculture Minister to make a statement in the next week regarding a very important point concerning paucity of rains in September-October, 1980 because of which khariff crops in 18 districts of Maharashtra have been adversely affected. Besides Rabi crops in sizeable areas suffered damages due to the moisture stress.

The total loss of crop production of kharif foodgrains, cotton and groundnut is to the tune of crores of rupees. The total number of villages affected, according to *Paisewari* Estimate is about 11,800.

Scarcity of drinking water is being experienced right now. The whole summer season is still to go.

The State Government has requested for the Central assistance of Rs. 28.62 crores: Rs. 20 crores for Relief Employment under the Employment Guarantee Scheme and Rs. 8.62 crores for Drinking Water Supply measures. In addition, Rs. 33.80 lakhs have been requested for giving Taccavi loans for purchase of fodder for cattle upto 31-3-81.

The Central team visited the State of Maharashtra in the second week of February, 1981. The team, according to my information, is generally satisfied with the field visits. I, therefore, urge upon the Government to make a categorical statement in the next week of Central Assistance to Maharashtra, as asked for. Thank you.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो भाइटम्ज के बारे में बोलना चाहती हूं। पहला विषय तो यह है कि केन्द्रीय सरकार के बनस्पति के बारे में 'प्रीवेन्शन ग्राफ एडल्ट्रेशन एक्ट' का संशोधन कर के बनस्पति मैन्यूफैक्चरर्स को "विटामिन ए" उसमें बढ़ाने के लिये मजबूर किया था। लेकिन पिछले नवम्बर में उन को इस से एक्जैम्पृट करने के लिये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है। इस के विरोध में सारे देश की कन्ज्यूमर-आर्गेनाइजेशन्ज प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारे देश में सालाना 40 हजार बच्चे विटामिन ए और मैलन्यूट्रीशन की वजह से अंधे होते हैं या उन को नाइट-ब्लाइण्डनेस हो जाती है। होना तो यह चाहिये था कि सरकार को भी खाना मिलता है उस को ज्यादा से ज्यादा फोर्टिफाई करे, जैसे साल्ट में आयोडीन मिलाया जा सकता है, जैसा दूसरे देशों में होता है। लेकिन हमारी सरकार वाइटेमिन-न्युट्रेटिव-फूड बनाने के बदले जो मिलता है उस में से ही वाइटेमिन निकालने की कोशिश कर रही है। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में मैंने जो काल एटेन्शन दिया है, उस पर अगले सप्ताह में बहस होनी चाहिये।

हमारी यह भी डिमांड है कि ता० 12 को वनस्पति मैन्यूफैक्चरर्स के साथ आप का जो डिस्कशन होने जा रहा है उस में कन्ज्यूमर-रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी बुला कर, उन को साथ ले कर प्राइस और दूसरी बातों के बारे में डिस्कशन करें।

मेरा दूसरा आइटम यह है कि दिल्ली में कोयले की कीमत चार बार बढ़ाई गई है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 1972 में हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया था कि रिटेलर्स और भारत-कोकिंग-कोल के बीच में इन्टर-मीडियरीज की जरूरत नहीं है। लेकिन 1978 में उन लोगों ने एक एशोसियेशन बनाई और वहीं से उन को कमीशन देने की शुरुआत हुई। पहले 2 रुपये प्रति-मीट्रिक टन दिये जाते रहे, उस के बाद 4 फरवरी से 2 रुपये से बढ़ा कर 17 रुपये कर दिये गये और उस के बाद फिर 17 रुपये से बढ़ा कर साढ़े-उन्नीस रुपये कर दिये गये हैं। उन की पहले जो मरी हुई आर्गेनिजेशन थी, फिर से "कोल डीलर्स सिंडिकेट" बना कर उस में कमीशन देने की कोशिश की है। इस तरह से कन्ज्यूमर्स को लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहती हूं कि इस के बारे इन्वेस्टीगेशन को जाय तथा इस पर पूरी तरह से डिस्कशन होना चाहिये और जो सच्ची बात है उस के ऊपर प्रकाश डालना चाहिये।

मेरे यही दो आइटम्ज हैं, जिन से कन्जूमर्स को बहुत तकलीफ हो रही है मैं चाहती हूं कि इन पर डिस्कशन होना चाहिये।

13.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

The House re-assembled after Lunch at five Minutes past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE —*Contd.*

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Sir, I just want to bring to the attention of the Minister for Parliamentary Affairs that in this House for the last three or four weeks we have been consistently from his side of the House, irrespective of differences, asking for a statement on the public sector employees' strike, which has been going on for the last one hundred and odd days. You know the importance of the whole thing. I do not understand the callous attitude of the Government regarding this very important strike which threatens the economy of the country, which also concerns lakhs of employees. This is the only point I would 'ike to make submission on.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अगले सप्ताह के लिये दो विषयों की सूचना आपके पास लिख कर भेजी है और मैं उसको ही पढ़े देता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are going to read the entire thing.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Yes. You always say like that, therefore I have written.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Two or three minutes.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Only one page. That is all.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only one page you are going to read.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Two lines in the second page.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से दिल्ली, बम्बई, पटना आदि बड़े शहरों में राशन, चीनी आदि नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को आसमान छूते मूल्यों पर वस्तुएं खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अभी हाल में मैं पटना गया था जहां ज्ञात हुआ कि राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, चीनी ठीक समय पर सप्लाई नही की जाती। राशन के दूकानदारों की शिकायत है कि उन्हें सरकारी अन्न भंडारों से समय पर और आवश्यकता के अनुसार गल्ला आदि नहीं दिया जाता। इस प्रकार की बात सरकारी अधिकारियों से सुनने को मिलती है। बहुत से स्थानों पर राशन के कार्ड भी नहीं दिये गये हैं। अत: दुकानदार सारी सामग्री चोर बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार की शिकायत मुझे पटना जिले के मालसलामी और चौक थानों के जल्ला क्षेत्र से मिली है। लगभग पचास हजार की आबादी में राशन कार्ड किसी को भी नहीं दिया गया है। कहने पर संबंधित अधिकारी आश्वासन दे कर छुट्टी पा लेते हैं। यह सिलसिला 6 माह से चल रहा है। इस विषय पर बहस होनी चाहिये।

बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों से राजनीतिक हत्याओं के समाचार लगातार मिलते रहते हैं। विरोधियों का रूप शारीरिक से सफाया करना ऐसी हत्याओं का उद्देश्य है। बिहार में पिछले वर्षों में पचास से अधिक राजनीतिक हत्यायें की गई हैं। सब से बड़ी चोट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों समेत दर्जनों नेताओं एवं कार्यकर्त्ताओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल में किसी भूतपूर्व एम० एल० ए० की हत्या की गई। आंध्र प्रदेश के किसी निर्दलीय विधायक को जान से मार दिया गया। अत: इस अत्यावश्यक विषय पर भी चर्चा होनी चाहिये। यह सिलसिला बहुत चल रहा है।

I mean political murders as distinct from other murders.

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): अगले सप्ताह के कार्यक्रम में दो विषय जोड़े जाने का मैं अनुरोध करता हूं। एल० आई० सी० के कर्मचारियों के वेतनों में हुई कटौती पर बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको देखते हुए पूरे देश के मजदूरों में यह आशंका है कि सरकार वेतन फ्रीज की नीति अखत्यार करेगी। इसलिए अखिल भारतीय पैमाने पर वेतन नीति निर्धारित करने के सवाल को अगले सप्ताह के एजेंडा में जोड़ा जाए।

महिलाओं के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं। उनके उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि नौकरियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस विषय को भी अगले सप्ताह के एंजडे में रखा जाना चाहिये।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: (Bombay North-East): More than one year has passed, of this House and of this Government. And you will recall that in every session, we have admitted a motion, put it on the agenda—for the discussion of the Vaidyalingam Commission's report. But it is always scheduled for the last

date, and as the last item. And by the time it comes, these people fillbuster, the time is extended and the thing gets out of the agenda. Last time also, the same thing happened. We were prepared to sit till midnight, and said: "We will discuss it." In the last session—I think, Sir, you were in the Chair; you would remember vividly—they got a motion moved saying that this must be put off for the next session. The next session has come. I don't see anything of it. I have given notices under rules 184 and 193 on my own. Now I am expecting Government to come forward with their motion. But I have also done it.

What is serious is that Kuldip Nayar in Indian Express has carried an article on the front page, saying that Government is thinking of prosecuting Mr. Morarji Desai and Mr. Kantibhai Desai, and of course, Gayatri Devi, for whom I hold no brief as such—because I don't know (*Interruptions*); I have not looked at that part of the report. I have only looked at that part relating to Morarji Desai; yes, naturally because Gayatri Devi has got many people to defend on that side. I am also prepared to join (*Interruptions*). We have to choose. Time is limited. There is the question of time, which is scarce. And it has to be efficiently allotted, to get the best results. (*Interruptions*) so, you defend her. (*Interruptions*) I am interested in defending one of them, viz. Morarji Desai —by implication Kanti Desai.

I am asking the Government and the House to allot time for a discussion on this—not at the end of the session, not as the last item, but as the first time.

I know Mr. Morarji Desai today has become a very popular person in the country. (*Interruptions*). And this Government is getting very nervous.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has he become popular just now?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He has become the most popular, just now. We expected that; specially after ceasing to be the Prime Minister, his stature has gone up. They have got nervous. They feel that somehow he should be maligned. This kind of thing—how can we put up with? Then it comes in the newspapers that they want prosecution. We don't see any prosecution. If they want to prosecute him let them prosecute; do it quickly. Do they have any material? If they have any material, let them come before this House and present it. Mr. Morarji Desai is completely innocent; and these people have nothing to pin point on him. So, they go on dragging the matter and not bringing it to any conclusion. I want that the matter should be brought to the conclusion. If they do not bring it forward in the coming two weeks, then we will have to think of some unorthodox way of getting them to agree. I don't think you would like that.

I am allowed to raise three items because Mr. Mhalgi had raised only one item.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only two.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Mr. Mhalgi had raised only one.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, only two.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Is it not transferable ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No; now the Gujral Committee Report.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Again there is something about the newspapers. *The Indian Express*, of course, is a good paper; it does a very good work. I have a complete appreciation for it. (*Inter-

[Dr. Subramanian Swamy]

ruptions) There is a news item that the Gujral Commission's Report on Urdu has been put aside.

AN HON. MEMBER: . That is an old story.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : It is an old story which is continuing. There are some allegations also in that Report about what happened during the Janata rule, which is not correct. On the top of it, we have another Gopal Singh Panel Report on minorities, muslims, SC and weaker sections, etc., this report has come. Then Mr. Ansari resigned or his term expired and you did not think it fit to extend it. You appointed somebody else. There is a parallel body. So, the whole thing is in a confusion and the minorities are in a greater confusion plus the fact that pro-Soviet Lobby created a chaos in the Aligarh Muslim University about which you should take notice. So, all this put together, I would like that this whole issue of Urdu, Gujral Commission's Report plus Gopal Singh Commission's Report should be discussed in this House at the earliest opportunity.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I have got two points to be included in the agenda for next week. As you know, on many occasions, the hon. Minister of Law, Justice and Company Affairs a had declared in this House that the Government had under consideration several proposals on electoral reforms in the country. You also know that there is an increased influence of money power in the elections of our country. Therefore, I want that the Government should make a statement as to what are the difficulties on their part to come to a definite conclusion with regard to various proposals regarding the electroral reforms in our country.

The second point is all the more important. As you all know, there has been increasing military presence by the United States of America in the Indian Ocean recently. There are reports in the newspapers which suggest that they have already started expanding Diego Garcia in order to facilitate the deployment of B 52 against India and other littoral countries. The situation is very grave because of the increasing presence of the United States of America in the Indian Ocean ; and the Government's position regarding Diego Garcia had already been diluted by the stand taken by the Government of India in the recent Non-aligned Conference held in New Delhi. Therefore, the House demands that there should be a statement on this or a subject included in the agenda for the next week so that we can make our point of view in this regard.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो विषयों पर सूचना दी थी। पहला विषय तो यह है कि कितना भी बड़ा दावा किया जाये किन्तु बन्धुआ मजदूरों की समस्या का कोई निदान अभी तक नहीं निकला है। 25 फरवरी के अखबार में हरियाणा में बन्धुआ मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ समाचार आये थे, लेकिन उतना ही नहीं मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने के बांदा गांव की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जहां हरिजनों को बांदा गांव से हटाकर छिवाही मौजे में बसा देने के सरकार के आदेश को वहां की सामन्तवादी शक्तियों ने रोक रखा है और उनको अभी भी भी बन्धुआ बनाया हुआ है। उस आदेश का कार्यान्वयन अभी तक रोके रखा गया गया है। वहां मजदूरों और हरिजनों की संख्या लगभग 4 हजार के आसपास है।

दूसरा विषय, जिसके बारे में मैंने सूचना दी है, डाक-तार विभाग में काम

करने वाले ई डी–एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंन्टल–कर्मचारियों से सम्बन्धित है। ई डी कर्मचारी विभागीय कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन यदि उन दोनों के वेतन और सुविधाओं की तुलना की जाये, तो आपको पता चलेगा कि उन ई डी कर्मचारियों की हालत कितनी दयनीय है। ई डी कर्मचारियों को प्रति मास केवल 105 रुपये वेतन मिलता है जबकि विभागीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रति मास है। इसके अलावा वर्दी, अवकाश, पेन्शन और महंगाई भत्ते की सुविधायें भी उन्हें उपलब्ध हैं। दोनों वर्गों के कर्मचारियों के काम में समानता है फिर भी ई डी कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव बरता जा रहा है। इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूंगा कि अगले सप्ताह सदन में इस पर बहस की जाये।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के कई जिलों में जांडिस रोग का प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में चार हजार लोग इससे पीड़ित हैं। बिहार गवर्नमेंट की ओर से इस रोग की रोक-थाम की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस बात की छान-बीन करने की आवश्यकता है कि इस रोग के फैलने का क्या कारण है और इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं। अगर समय पर उपचारात्मक पग न उठाये गये, तो इस रोग के एक महामारी के रूप में दूसरे इलाकों में भी फैल जाने की आशंका है। इस लिए मैं चहाता हूं कि अगले सप्ताह इस विषय पर बहस की जाये, या सरकार इस बारे में वक्तव्य दे कि इस रोग की रोक-थाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चीनी मिलें हैं जिनके मालिकों पर किसानों का गन्ने का करोड़ों रुपया बकाया है कृषि मंत्री ने यहां बयान दिया था कि हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी मिलें बन्द हो गई हैं, लेकिन अभी तक किसानों के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इस विषय को शामिल कर लिया जाये, ताकि इस बात के उपाय निकाले जायें कि किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कैसे कराया जाये और चीनी मिल–मालिकों पर जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाये।

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : Sir, while supporting the point which Comrade Rajan has made in regard to the public sector employees' strike, I would like to suggest to the Government that either they come with a statement or enable us to have a discussion by any other means. I do not think this matter should be allowed to drag on in the manner in which it has been dragging on.

Having said that, there are two issues which I would like to raise. One is the Economic Administration Reforms Commission that has now been constituted by the Government. For the last eight or ten days, we were reading in the newspapers very well leaked out stories that Government is considering such a proposal; it is reported to be under consideration ; services of some very distinguished economists are now to be secured; some new jobs are being made available for some retired people and so on and so forth. These leaks continued for about eight or ten days. Then suddenly yesterday evening at 6 o'clock, I think the Minister of State for Parliamentary Affairs or I do not know whether it was the Deputy Minister for Finance, but someone produced this paper which has been circulated this morning along with our Parlia-

[Shri George Fernandes]

ment papers, which tells us that the Government has adopted a resolution, that a certain Commission has been set up with Mr. L.K. Jha, former Governor of Jammu & Kashmir as the Chairman and Mr. Tirumalai and Dr. Hanumantha Rao are the Members. It will have a Secretary and the Commission may, with the approval of the Government, coopt *ad hoc* members on a part-time basis as well as enlist assistance of experts and institutions and so on and so forth. The Government is supposed also to refer to this Commission various matters pertaining to economic administration, economic growth, etc., though the Commission would be purely an advisory body. In the first instance, four items have already been given to this Commission for its report. There are a number of questions that arise. Firstly, if you had an idea to set up a commission of this nature rather than go on leaking out these stories, you should have come to this House and said, "This is what the Government is intending to do", because I am assuming that this is a very important decision of the Government. Government may say, this is a very casual thing; that Mr. Jha had no other job; we needed a Nehru in Srinagar; so we put a Nehru there and we brought Jha out and we wanted to have some sinecure position for him; so we have set up this commission; it is not important decision; it is one of those casual decisions of the Government and therefore, it was not necessary for us to come before the House. Or, this is a very important decision where you are taking certain new policy initiatives; you are concerned with economic administration, with economic reforms and so on, in which case any major policy decision you had no business to leak out to the newspapers that this is what we are thinking, what we are planning, Mr. Jha is being brought in and so on. Therefore, I would like the Government to tell us what exactly is the significance of this commission.

Secondly, when you have set up this commission, the Finance Minister presented the budget only a few days ago and we are now going to discuss it. Looking at the terms of reference of this Commission, I would like to know whether the budget proposals are the last word for the coming twelve months or whether they are going to be modified, because one finds here that the terms of reference include :

"(i) tax administration, its rationalisation and improvement ;

(ii) use of non-tax devices for raising the level of savings."

We, of course, have the black money bonds which I presume, is one of the non-tax devices and the Finance Minister's ingenuity in these matters, we heard a bit about it the other day. Are we going to have more such devices—non-tax devices—for raising the level of savings ? Then there are two other items which are equally important. The question therefore arises whether this budget can be seriously discussed. Then you have the Five Year Plan which you have already presented. The National Development Council has endorsed it. Is this super Planning Commission or something that is subservient to the Planning Commission ? Is the plan going to be affected or modified with the setting up of this Economic Administration Reforms Commission ? What is going to happen to the Plan and to the Planning Commission we would like to know.

One other question arises out of the appointment of this commission. One also sees that this Commission is going to be directly under the Cabinet Secretariat.

MR DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI GEORGE FERNANDES : Either you also take the view that this is a casual thing to get a sinecure job for Mr. Jha or you must accept my proposition that this is a major policy decision of the Government. I am not pro-

pared to believe that this is just a sinecure position. I believe it is a serious matter. I must, therefore, convey to you and through you to the Minister of Parliamentary Affairs that here is a serious matter that needs to be discussed immediately and every other business before the House can wait. We must discuss this matter.

The Finance Ministe is sitting here. He is the man who is primarily concerned with the budget. He is the man whose budget we are going to discuss. Here is a Commission which is under the Cabinet Secretariat, directly reporting to the Prime Minister. What exactly is the Cabinet Secretariat becoming? Is it becoming a Super Cabinet? Is it now once again getting into its hands all those powers which once were given to it and we know with what consequences, in 1974-75 and 1976 where exactly are we going ? I would, therefore, want that the Minister of Parliamentary Affairs should take up this matter immediately and list it as a priority matter for discussion next week.

My last point pertains to the Minorities Commission. The Chairman of the Minorities Commission has resigned. His resignation was forced. Every body knows it, though I am told and the Home Minister has been making statements here, there and everywhere, "No, no. It was not forced. It was because his term expired." We know that his term had not expired. He had a three year term as Chairman. Why did Mr. Ansari have to resign? What were the reports that he had given which displeased this Government ? What were the decisions of the Minorities Commission which angered this Government and made this Government put pressure on Mr. Ansari to resign? We have had a number of reports from the Minorities Commission. I do not know how many of them Government has cared to read, but we are certainly concerned with those recommendations and we want to discuss them.

I hope the Minister of Parliamentary Affairs will take up seriously these two issues, along with the issue raised by Comrade Rajan and put up them for discussion next week.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब को शिक्षा सुलभ नहीं है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद एजूकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बेरोजगारों की पलटन बढ़ती जा रही है। ऐसी शिक्षा जोकि सस्ती न हो, जोकि गरीबों को सुलभ न हो, जोकि रोजगार देने वाली न हो और जिसका इंडियन कल्चर से कोई वास्ता न हो ऐसी शिक्षा में सुधार लाने के लिए अगले सप्ताह यहां पर विचार होना चाहिए ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आज किसानों की समस्यायें बराबर उलझती जा रही हैं, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनके सामने खाद, बिजली और पानी की समस्यायें हैं जिन पर कोई और नहीं हो रहा है। पिछली बार भी एक बहुत बड़ी किसान रैली हुई थी और अभी अभी आज भी जनता (एस) के राज-नारायण जी के नेतृत्व में किसान रैली हुई है। वहां पर राज नारायण जी, इस संसद के दो माननीय सदस्य श्री मनीराम बागड़ी एवं चौधरी मुल्तान सिंह तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव, जोकि हजारों किसानों के साथ संसद की तरफ अपनी बात कहने के लिए आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों की सख्या में पुलिस लगी हुई है। दसियों हजार किसान जोकि संसद की तरफ बढ़ रहे हैं उनको पुलिस गाड़ियों में बन्द करके जेल की तरफ भेज रही है। किसान एक तरफ आयें को

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

उनको फ्री रेलें मिलें, फ्री बसें मिलें लेकिन जो हमारी बसेज ग्रा रही थी, जो हमारे किसान ट्रैक्टर्स पर ग्रा रहे थे उनको चारों तरफ से रोक दिया गया ग्रौर ग्रागे बढ़ने नहीं दिया गया। हर चौकी पर उनको रोक दिया गया है। ऐसी दशा में किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? एक तरफ तो किसानों के नेताओं को बन्द किया जाए, उनको क्रश किया जाए ग्रौर दूसरी तरफ नकली किसान रैलीं को सरकारी सहायता दी जाए—यह ऐसी समस्यायें हैं जिस पर मैं कहूंगा कि ग्रगले सप्ताह तुरन्त चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) इस सदन के दो माननीय सदस्य ग्रौर किसानों के माने हुए नेता, श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है.... (व्यवधान) ग्राप हंस रहे हैं ग्रापकी तो नकली रैली हुई थी, ग्रापके लोग रसगुल्ला खाने वाले, मुर्गा खाने वाले ग्रौर रेलों में लूट मचाने वाले लोग थे। ग्राप इन ग्रनुशासित किसानों को भी देखिए जोकि ग्रपने खर्चे से यहां पर ग्राए हुए हैं। वे फटे हाल तो जरूर हैं, जो मातायें बहनें ग्राई हुई हैं उनके तन पर मैले कपड़े जरूर हैं पर यह किसानों की ग्रसली रैली है। तुम्हारी रैली नकली थी। यह रैली किसानों का सही नेतृत्व करती है। (व्यवधान) ग्राप फटे हाल किसानों पर हंस रहे हैं। (व्यवधान) मेरा ग्रनुरोध है कि इसको प्रोसीडिंग्ज, में ग्राना चाहिए ग्रौर ग्रगले सप्ताह किसानों की समस्याओं पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए।

SHRI GEORGE FERNANDES: What about the arrest of two hon. Members of Parliament ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not allowing you.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (ग्रांवला): मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए जाऊंगा। मैं इस सदन से वाक ग्राउट करता हूं ग्रौर ग्रपनी गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूं।

14.34 hrs.

(Shri Jai Pal Singh Kashyap then left the House)

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH : I am extremely grateful to the hon. Members because they have made valuable suggestions. Some of the hon. Members have asked the Government to make statements on certain issues. I have noted your points. I will go through the proceedings and bring those points which I feel necessary to the notice of the Business Advisory Committee. I will communicate you other points to the concerned Ministers.

14.35 hrs

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1980-81.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY) : I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1980-81.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1977-78

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY) : I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 1977-78.